

भागलपुर से गंगा की धारा को दूर
हटा जाना

1654 डा० रामजी सिंह : क्या
श्री वि. सी. सिंघाई मंत्री यह बताने की
कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का भागलपुर नगर
से गंगा की धारा दूर हटा जाने से व्यापार
और वाणिज्य, जनस्वास्थ्य और स्थानीय
सौन्दर्य को अति पहुंचाने के बारे में जानकारी
है।

(ख) यदि हां तो क्या उस के निवारण
के लिये गंगा की धारा बदल कर शहर के
किनारे लाने का सरकार का विचार है,

(ग) यदि हां, तो अब तक और यदि
नहीं तो इस के क्या कारण हैं

(घ) क्या बरारोघाट के तटबन्ध
व रम्ब रखाव पर सरकार का लाखों रुपया
खर्च करने पड़ते हैं और

(ङ) यदि हां, तो क्या गंगा की धारा
शहर के किनारे लाकर यह खर्च बचाया
जा सकता है और यदि हां, तो क्या सरकार
का विचार इस मामले पर विचार करने
का है क्योंकि शहर के निकट गंगा का स्थिर
किनारा है ?

डा० श्री वि. सी. सिंघाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह
बरनाला) (क) से (ङ) भागलपुर के
निकट गंगा नदी के मार्ग को बदलने के संबंध
में बिहार सरकार से अभी तक कोई रिपोर्ट
प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार से उपलब्ध
सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है
और प्राप्त होते ही यह सूचना सदन के समक्ष
प्रस्तुत कर दी जायेगी।

Improvement in the Backward areas
of Rajasthan

1655 SHRI S S SOMANI Will the
Minister of WORKS AND HOUSING
AND SUPPLY AND REHABILITA-
TION be pleased to state

(a) whether proposals for tackling
the drinking water supply problems
in rural areas have been submitted
by the Government of Rajasthan, and

(b) if so the details regarding the
assistance provided by the Central
Government to the State of Rajasthan
during the current financial year in
this regard?

THE MINISTER OF WORKS AND
HOUSING AND SUPPLY AND RE-
HABILITATION (SHRI SIKANDAR
BAKHT) (a) Yes Sir

(b) A sum of Rs. 200 lakhs was
allocated to the States of Rajasthan
in September 1977 under the centrally
sponsored Accelerated Rural Water
Supply Programme for providing
drinking water in problem villages. An
additional amount of Rs. 50 lakhs has
also been allocated for providing
drinking water to problem villages
situated in desert areas during the
current financial year.

A sum of Rs. 1.30 lakhs (Rs. 50
lakh, for execution of works plus
Rs. 1.50 lakhs for setting up of an
Investigation Unit and Rs. 80,000 for
a Monitoring Cell) has been released
to the Government of Rajasthan in
October last as the first instalment of
Central assistance under the above
mentioned Programme during the cur-
rent financial year.

Reconstitution of APC

1656 SHRI P RAJAGOPAL NAIDU
Will the Minister of AGRICULTURE
AND IRRIGATION be pleased to state

(a) when the Agricultural Prices
Commission was constituted,